

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या 2021/194

प्रकरण संख्या 53/21

अनवान

श्रीमती नानीबाई

बनाम

श्री मोहन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

— : आदेश : — दिनांक: 29.10.2024

1. प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने आप न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (1) (4) राज. टि.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र टाईम बार्ड होकर मिथ्या अभिवचनों के आधार पर बिना वादकारण उत्पन्न हुए प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उक्त वाद पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र की कलम संख्या 1 व 2 में मिथ्या व मनगढ़त अभिवचन किये हैं तथा वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट (क) व (ख) व वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जी स्वअर्जित खरीदशुदा एवं आवन्तनशुदा भूमि को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पैतृक सम्पत्ति बताकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो मिथ्या अभिवचन के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या 1 की परिशिष्ट (क) में अंकित आराजी न. 159 रकबा 9 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा दिनांक 29.03.1974 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1200/- बाहर सौ रूपये प्रतिफल के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा पिता टीला द्वारा खरीदा गया है उक्त तथ्य स्वयं वादीगण भी स्वीकार करते हैं तो उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति कैसे हो सकती है, जिसका कि वैध रजिस्टर्ड दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत है। इसी तरह से परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी न. 262 रकबा 2 बिघा, 268 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा भूमि, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा भूमि की संवत् 2004 की जामबन्दी में भेरा बल्द टीला साकिन देह शिकमी का इन्द्राज है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिताजी के नाम शिकमी के रूप में अकेले दर्ज थी, उसके बाद संवत् 2019 से 2021 की जमाबन्दी में भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर लगातार उनके अकेले का कब्जा काश्त चले आने से तथा उनके द्वारा भूमि को मेहनत कर विकसित करने से उनको शिकमी से खाते से मंजूरी होने का दिनांक 16.11.2012 का अंकन है तथा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर लगातार उनके अकेले का कब्जा काश्त चले आने से तथा उनके द्वारा भूमि को मेहनत कर विकसित करने से उनको शिकमी काश्तकार से खातेदारी अधिकार दिये गये जो प्रथम दृष्टया ही स्वयं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से

- प्रमाणित है तथा उक्त परिशिष्ट (क) व (ख) में अंकित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी का निधन होने के बाद उपरोक्त वर्णित दोनों आराजीयान नामान्तरण जसिये नामान्तरकरण संख्या 284/10.02.1983 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला गया यानि कि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता तथा उनका निधन के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त लगातार निर्वाह रूप से उक्त वर्णित आराजीयान खातेदारी हक व अधिकार से चली आ रही है।
2. यह कि वादीगण ने उनके पिता व प्रतिवादीगण के पिता के निधन होने व उक्त आराजीयान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज होने के करीब 30 वर्ष बाद यानि कि वर्ष 2013 में उक्त मिथ्या अभिवचन अंकित करते हुए बिना किसी आधार पर, बिना कोई वाद कारण पैदा हुए मात्र प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि से उनको महरूम करने के लिए उक्त मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है, जो प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। वादी ने अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजी न. 49 रकबा 2 बिघा 6 विस्वा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की है, बिना किसी ठोस आधार के मात्र कयासी आधार पर, मात्र सजरे के आधार पर स्वअर्जित सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति बनाने का मिथ्या प्रयास किया है तथा वादीगण ने जानबुझकर साविक आराजी न. 269 रकबा 1 बिघा 3 विस्वा भूमि जो आराजी न. 262 एवं 268 के पडौस में स्थित है, साविक आराजी न. 269 के हाल आराजी न. 507, 508, 509 एवं 510 कुल किता 4 रकबा 0.2500 है, होकर उक्त आराजी न. 269 को वाद पत्र में छिपाया है क्योंकि उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4-1/4 हक, हिस्सा है तथा वादी एवं अन्य प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/40 एवं 1/10 हिस्से का अंकन होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम का अंकन था, उनके निधन के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम अंकन हैं इससे भी स्पष्टतया इस बात को बल मिलता है कि वादी ने मात्र मिथ्या वाद पत्र बनाने की गरज से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता को कर्ता खानदान होने तथा पैतृक सम्पत्ति बता कर बिना कोई वाद कारण पैदा हुए उक्त खातेदारी अधिकारों की धोषणा का मयाद बाहर वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है, क्योंकि यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा पैतृक सम्पत्ति को कर्ता खानदान होने से तथा उस समय वादीगण के पिता के हिस्से को अपने अकेले के नाम से कराया जाता तो आराजी न. 269 में आज वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के नाम का अंकन नहीं होता जिससे भी स्पष्ट है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति को मिथ्या आधारों पर मात्र सजरा प्रस्तुत कर कयासी आधार पर पैतृक सम्पत्ति बता कर उक्त गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसका कि वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है, मात्र वाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न होना लिख देने मात्र से वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हो जाता है। इसलिये भी उक्त वाद पत्र प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है।
3. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम वर्ष 1983 में उनके पिता भेरा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति में उनके निधन के पश्चात खुले नामान्तरकरण के 30 वर्ष बाद वर्ष 2013 में उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है उक्त वाद पत्र मयाद बाहर होकर वादीगण ने अपने वाद पत्र में 30 वर्ष के लम्बे समय के बाद उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट एवं ठोस कारण दिन प्रतिदिन का अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत कर दिये जाने से वादीगण को उक्त 30 वर्ष के लम्बे समय की

- मयाद से छूट प्राप्त नहीं हो जाती है तथा वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में देशी का दिन प्रतिदिन कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है ऐसे में उक्त वाद पत्र पूर्णरूप से मयाद बाहर होने से प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।
4. प्रकरण में वादी/अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसमें बताया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से टाईम बार्ड नहीं है एवं न ही मिथ्या अभिवचनों पर आधारित है। वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह पूरी तरह से सही वाद कारण पर आधारित है एवं वादीगण का वाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के न्याय प्राप्ति में विलम्ब कारित करने के आशय से झूठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो पूरी तरह से खारिज योग्य है।
5. यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि की सारी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, जिस पर वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है एवं वादग्रस्त कृषि भूमि में पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण प्रकरण के निर्णय से ही हो सकेगा। वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह पूरी तरह से सही वाद कारण पर आधारित है एवं वादीगण का वाद किसी भी तरह से प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य नहीं है एवं न ही मिथ्या अभिवचनों पर आधारित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं यह कथन कर रहे हैं कि उनको महसूस करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे ही स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त वाद के निर्णय से वादीगण को अपने हक अधिकार प्राप्त हो जावेंगे तथा उपरोक्त वाद वास्ते कायमी तनकीयात के स्तर पर आ चुका है एवं इसके वाद वादीगण की साक्ष्य प्रारंभ होगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वास्तविक साक्ष्य को रोक कर देशी कारित करना चाहते हैं इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार का मिथ्या पत्र पेश किया है।
6. यह कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में सारे अभिवचन वाद पत्र में किये हुए हैं जिनका जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब भी वादीगण द्वारा दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद के एवं प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के निर्णय से ही पक्षकारों के वास्तविक हक अधिकार तय हो सकेंगे। वादीगण का वाद सही वाद सही वाद कारण पर आधारित है जो किसी भी तरह से मयाद बाहर नहीं है एवं न ही प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दरतावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उमय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये—

- I. AIR 2016 DELHI 120 DELHI HIGH COURT SURENDRA KUMAR VS. DHANI RAM AND ORS.
- II. RRT 2010(1) RRT 124 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER RANJEET KAUR & ORS. VS. BHAGWAN DAS & ORS.

8 पत्रपत्नी के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के अध्ययन से पाया कि अधिवक्ता द्वारा एक वाद अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। बताया कि वादग्रस्त आराजीगत 262, 268 कित्ता 2 रकबा 3 बिघा आराजी न 49 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दु परिवार अधिभाजित पैतृक जायदाद है जो हमार स्वर्गीय श्री टीला जी के समय से चली आ रही है तथा इस भूमि में टीला जी मरणोपरान्त टीला जी के दोनो ही पुत्र भेरा जी एवं वावरीया जी काविज होकर काश्त करने लग गये तथा भेरा जी के मरणोपरान्त भेरा जी हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काविज होकर काश्त कर रहे हैं। वावरीया जी के मरणोपरान्त वावरीया जी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा हक छोड़ दिये जाने से वादी संख्या 1, 2, 7 एवं वादी संख्या 3 के पिता रूपलाल हिस्से बराबर से काविज होकर काश्त करने लग गये। रूपलाल के फौत होने के बाद उसके हिस्से पर वादी संख्या 3 से 6 काविज होकर काश्त कर रहे हैं साथ ही आराजी न 159 रकबा 9 बिस्वा का 1/2 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के मोरूस वावरीया जी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मोरूस भेरा जी द्वारा संयुक्त रूप से खातेदार श्री नाथु जी खरीद किया गया एवं खरीद से ही हिस्से बराबर से काविज होकर काश्त करने लग गये। यह कि वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय टीला जी की फौत होने के बाद परिवार के कर्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी थे जिससे उक्त वादीगण के मोरूस वावरीया जी के हक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की निमित्त से वादग्रस्त भूमि में वादीगण के मोरूस वावरीया जी का नाम अंकन नहीं करवाया जायकि इस पैतृक कृषि भूमि में वादीगण के मोरूस वावरीया जी का नाम अंकित होना चाहीये था जिससे वादीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर बताया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट (क) व (ख) व वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की स्वअर्जित खरीदशुदा एवं आवन्तनशुदा भूमि को बिना किसी दस्तावेज़ी साक्ष्य के पैतृक सम्पत्ति बताकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो मिथ्या अभिवचन के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या 1 की परिशिष्ट (क) में अंकित आराजी न. 159 रकबा 9 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा दिनांक 29.03.1974 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1200/- बाहर सौ रूपये प्रतिफल के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा पिता टीला द्वारा खरीदा गया है उक्त तथ्य स्वयं वादीगण भी स्वीकार करते हैं तो उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति कैसे हो सकती है। इसी तरह से परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी न. 262 रकबा 2 बिघा, 268 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा भूमि, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा भूमि की संवत् 2004 की जामबन्दी में भेरा वल्द टीला साकिन देह शिकमी का इन्द्राज है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिताजी के नाम शिकमी के रूप में अंकित दर्ज थी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पेश की जिससे पाया की प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मोरूस भेरा पिता टीला द्वारा दिनांक 29.03.2074 को आराजी संख्या 159 रकबा 9 बिस्वा का 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जिससे स्पष्ट है कि आराजी संख्या 159 रकबा 9 बिस्वा के 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता भेरा पिता टीला

जिससे वादीगण का उक्त आराजी वाक्य कोई अधिकार साबित नहीं होता है न ही कोई वाद कारण उत्पन्न होता है। अधिवक्ता वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 262, 268 कित्ता 2 रकवा 3 बिघा 17 बिरवा व आराजी संख्या 49 रकवा 2 बिघा 6 बिरवा भूमि को पैतृक सम्पत्ति का कथन कहा जबकि मेवाड रजिस्ट्रार जमाबंदी संवत् 2005 में आराजी संख्या 262, 268, 49 प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मौरस भेरा प्लट टीला बोला सा देह शिकमी के नाम दर्ज रेकॉर्ड है तथा आगे चल कर जमाबंदी संवत् 2050-53 में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुई जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति नहीं है जिससे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति साबित हो। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2016 DELHI 120 DELHI HIGH COURT SURENDRA KUMAR VS. DHANI RAM AND ORS. में स्पष्ट किया है कि "This position of law along with facts as to how the properties are HUF properties was required to be stated as a positive statement in the plaint of the present case but if it is seen that except uttering amantia of the properties inherited by defendant no. 1 being ancestral properties and thus the existence of HUF, there is no statement or a single averment in the plaint as to when this HUF which is stated to own the HUF properties came into existence or was created." साथ ही स्पष्ट किया कि this court is flooded with litigation where only self-serving are made in the plaint of existence of HUF and a person being a coparcener in any manner pleading therein the requisite legally required factual details as to how HUF came into existence. It is a sinequa non that pleadings must contain all the requisite factual ingredients of a cause of action, and once the ratios of judgments of the Supreme Court in the cases of Chander sen and Yudhishter come in, the pre 1953 position and the post 1956 position has to be made clear, and also as to how HUF and its properties came into existence whether before 1956 or after 1956. It is no longer enough to simply state in the plaint after passing of the Hindu Succession Act, 1956, that there is a joint Hindu family or an HUF and a person is a coparcener in such an HUF/joint Hindu family for such person to claim rights in the properties as a coparcener unless the entire factual details of the cause of action of an HUF and each property as an HUF is pleaded." माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि याचिका में कार्यवाही

न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर प्र.सं. 53/21 अलखन भागीवाड़े बनाम अलख निषण्य दिनांक 29-11-2024  
के समस्त आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिये मात्र साथ ही सम्पत्ति की स्थिति भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। याचिका में केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद में यह स्पष्ट नहीं किया कि सम्पत्ति किस प्रकार संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि जिससे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति नहीं है अधिवक्ता वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति साबित हो। अतः प्रकरण में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 संपटित धारा 151 जोड़ी का स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निषण्य खुले ईजलास सुनाया गया।

## डिकी व मुकद्द में इब्दाई

(आ 20 साल 6-7 जान्वा नीवासी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद सख्या : 53/21 (वाद)

**GCMS NO: 2021/194**

### अनवान

1. मु नानीबाई पत्नि स्व श्री बाबरिया जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
2. श्री भगवानलाल पुत्र श्री बाबरिया जाति रेगर (बोला) के बजाय-
  - 2/1 श्री शम्भुलाल पुत्र स्व श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
  - 2/2 श्री कैलाश पुत्र स्व श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
  - 2/3 श्री महेश पुत्र स्व श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
  - 2/4 श्रीमती रेखा पुत्री स्व श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
  - 2/5 श्रीमती गंगा पत्नि स्व श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
3. मु गोपीबाई पत्नि श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
4. श्री किशनलाल पुत्र श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज के बजाय
  - 4/1 श्रीमती मंजू पत्नि स्व श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
  - 4/2 श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
  - 4/3 श्री अर्जुन पुत्र स्व श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
  - 4/4 श्रीमती मनीषा पुत्री स्व श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
- 4/2 से 4/4 जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती मंजू पत्नि स्व श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
5. श्री सुरेश पुत्र श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
6. श्रीमती निमला पुत्री श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
7. श्री गणेश पुत्र श्री बाबरिया जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज के बजाय-
  - 7/1 मु भवरीबाई पत्नि स्व श्री गणेश जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।

- 7/2 श्री शिवलाल पुत्र स्व श्री गणेश जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
- 7/3 श्री यशवन्त पुत्र स्व श्री गणेश जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
- 7/3 जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता मु. भंवरी पत्नि स्व. श्री गणेश जाति रेगर निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।

### बनाम

1. श्री मोहन पुत्र श्री भेरा जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
2. श्री उकार पुत्र श्री भेरा जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
3. श्रीमती कोशी पुत्री श्री बावरिया जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
4. श्रीमती लाली पुत्री श्री बावरिया जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।
5. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज ।

उपस्थित:-

- 1 श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता वादी ।
- 2 श्री ललीत जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी ।

### वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 53/21 (वाद)

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसा लकतई रुबरु श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिमजानि वमुद्दागलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिब्री दी जाती है कि - परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया। दस्तावेज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.10.2024 को जारी की गई।